में 322 करोड़ तक की लागत की सहायता राशि भारत सरकार के अंतर्गत, विशेषकर इस स्कीम के अंतर्गत दी गई है और पिछले तीन सालों में महाराष्ट्र में दो विशेष स्थानों, धुले और इचलकरंजी में textile scheme के अंतर्गत पार्कों की व्यवस्था में भारत सरकार की ओर से सहायता दी गई है।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि गुजरात में बहुत सारे लोग हथकरघा कार्य में लिप्त हैं। वे अपने घरों में कपड़े, शॉल वगैरह बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई ऊन खरीदनी पड़ती है, तो कोई डायरेक्ट सब्सिडी या ग्रांट नहीं मिलती है। माननीय मंत्री जी भी इस बात को जानती हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं और मेरा ऐसा प्रस्ताव भी है कि जब वे इसको मार्किट से डायरेक्ट परचेज़ करें, तो उनको डायरेक्ट ग्रांट मिलनी चाहिए।

श्री उपसभापति: आप सवाल पूछिए, प्रस्ताव मत दीजिए।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : उपसभापति जी, आपके माध्यम से आदरणीय सांसद ने सदन के समक्ष जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह प्रस्ताव विशेषतः हैंडलूम वीवर्स के संदर्भ में है। जब हमारी कच्छ में हैंडलूम वीवर्स से वार्ता हुई, तो ध्यान में आया कि वे एक्रिलिक थ्रेड इस्तेमाल करना चाहते हैं, वूल से थोड़ा डायवर्ट कर रहे हैं। वर्तमान में नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत 10 प्रतिशत की सब्सिडी हैंडलूम वीवर्स को नेचुरल थ्रेड और फाइबर में दी जाती है। चूंकि एक्रिलिक material उसकी संरचना में नहीं आता है, इसलिए वर्तमान में यह सहायता हैंडलूम से परे हटकर देना थोड़ा-बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कच्छ के जितने वीवर्स हैं, हमने उनके साथ विशेषतः हैंडलूम विभाग के माध्यम से और गुजरात सरकार के माध्यम से यह प्रस्तावना की है कि अगर कोई सब्सिडी की दृष्टि से हैंडलूम सेग्मेंट में आता है, तो उसे विशेष यार्न की पास बुक देकर सब्सिडी की सुविधा दिलवाने का हमारा पूरा प्रयास है। उन्हें यह सब्सिडी दिलवाने का मेरा पूरा प्रयास है और मैं उस प्रयास में एक हद तक सफल भी हो पाई हूं।

श्री उपसभापति: Q. No. 353 श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम। अनुपस्थित। Are there any supplementaries?

* 353 [*The Questioner was absent.*]

E-passport for citizens

*353. SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has proposed to introduce e-passport for the citizens of the country in the near future;

(b) if so, the purpose of introduction of e-passport in place of the present system; and

1.00 P.M.

(c) the manner in which it would be different from the present form of passport and the details of advantages of using such passport?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Yes. The Ministry has plans to issue chip-enabled e-passports to citizens with advanced security features.

The personal particulars of the applicants would be digitally signed and stored in the chip which would be embedded in the present form of physical passport booklet. In case anyone tampers with the chip, the system shall be able to identify it resulting in the failure of the passport authentication.

The Government has given its approval for procurement of electronic contactless inlays for manufacturing of e-passports to India Security Press (ISP) Nashik. In this regard, ISP, Nashik has been authorized to float a global three-stage tender for procurement of International Civil Aviation Organisation (ICAO)-compliant electronic contactless inlays along with its operating system, which is required for manufacture of e-passports. Manufacture of e-passport will commence on the successful completion of the tendering and procurement process by ISP, Nashik.

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): Sir, the answer is very explicit but I have a supplementary question. Has the Government already decided the time-frame which proposes to allow the passport holders of this country to change over once the security features are in place and the order is supplied to the Government?

DR. S. JAISHANKAR: Sir, I would like to inform the hon. Member, through you, that, at this moment, we are still in the last stages of the tender. The tender has two components, an international component and a domestic component. Once we open the tender and make the decisions, it is only then that we can come to the timeline within which in the first phase we want to bring in about 22 million electronic passports. So, we have not reached that stage.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall move to Q. No. 354.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, it is 1 o' clock.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over. The House stands adjourned for lunch till 2.00 p.m.

———